

राज्यसभा
तारांकित प्रश्नपत्र संख्या 190
16 दिसम्बर 2015 को उत्तर के लिए

इस्पात के उत्पादन और निर्यात हेतु लक्ष्य

*190. श्री मेघराज जैन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन, घरेलू उपभोग एवं निर्यात के लिए क्रमशः निर्धारित और हासिल लक्ष्यों का ब्यौरा क्या-क्या है;
- (ख) इस संबंध में अगले तीन वर्षों के लिए क्या संशोधित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और
- (ग) क्या सरकार द्वारा आगामी वर्षों में इस्पात के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात और खान मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“इस्पात के उत्पादन और निर्यात हेतु लक्ष्य” के बारे में श्री मेघराज जैन, संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *190 के भाग (क) से (ग) के संबंध में विवरण

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और इसलिए इस्पात के उत्पादक घरेलू खपत और निर्यात के लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किये जाते हैं। इस्पात के उत्पादक घरेलू खपत और निर्यात से संबंधित निर्णय अलग-अलग इस्पात उत्पादकों द्वारा बाजार मांग और उनके अपने-अपने अन्य वाणिज्यिक सोच विचारों के आधार पर लिये जाते हैं। तथापि, उत्पादक घरेलू खपत तथा निर्यात के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

आंकड़े मिलियन टन में

क्रूड इस्पात		फिनिशड इस्पात	
वर्ष	उत्पादन	निर्यात	वास्तविक खपत
2012-13	78.42	5.37	73.48
2013-14	81.69	5.98	74.09
2014-15	88.98	5.59	76.99

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

(ग): इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है। तथापि, सरकार समर्थकारी नीतियों के द्वारा उद्योग को सुविधा जनक बनाने का प्रयास करती है। सरकार ने इस्पात निर्माण की लगभग 110 एमटीपीए क्षमता को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाकर 300 एमटीपीए करने का एक महत्वाकांक्षी विजन निर्धारित किया है। सरकार ने उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए “माइन्स एण्ड मिनेरल (डेवलपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट एक्ट 2015” भी लागू किया है। जहाँ तक इस्पात के निर्यात का संबंध है, सरकार घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है, ताकि विदेशों के बाजारों में इस्पात का निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक हो सके। घरेलू इस्पात उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्न लिखित उपाय किए हैं:-

- सरकार ने इस्पात के गुणवत्ता पूर्ण उत्पादों को सुनिश्चित करने लिए दिनांक 12.03.2012 को ‘स्टील एण्ड स्टीवल प्रोडक्ट- (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर अधिसूचित किया है, जिसे अंतिम बार दिनांक 04.12.2014 को संशोधित किया गया है।
- लोह अयस्क से समृद्ध झारखण्ड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में बड़ी क्षमता की ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीगकल (एसपीवी) फ्रेमवर्क अपनाया गया है।

- (iii) सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों ने इस्पात उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए विस्तार योजनाएं हाथ में ली हैं। सेल ने अपनी क्रूड इस्पात उत्पादन क्षमता को 12.8 एमटीपीए से बढ़ाकर 21.4 एमटीपीए करने के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार योजना हाथ में ली हैं। आरआईएनएल ने अपनी क्षमता को 3 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए करने के लिए विस्तार कार्य हाथ में लिए हैं। एनएमडीसी ने 3 एमटीपीए क्षमता के एक नए इस्पात संयंत्र की स्थापना का कार्य आरम्भ किया है।
- (iv) केन्द्रीय बजट में फ्लैट और नॉन फ्लैट दोनों इस्पात पर सीमा शुल्क की उच्चतम दर प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।
- (v) सरकार ने जून, 2015 में स्टेनलैस स्टील के कठिपय किस्मों के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों के चीन (\$ 309 प्रति टन), कोरिया (\$ 180 प्रति टन) और मलेशिया (\$ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई है।
- (vi) सरकार ने सितम्बर, 2015 में 200 दिनों की अवधि के लिए 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वार्टर में नान अलॉय और अन्य 5 अलॉय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों पर 20 प्रतिशत का अनन्तम सुरक्षोपाय शुल्क लगाया है।
